स्कूल एजुकेशन कॉन्क्लेव में संबोधन

(11 सितंबर 2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित **सतत विकास एजेंडा-२०३०** के अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, **पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही** के मूलभूत स्तंभों पर बनाई गई है।

इसमें **शिक्षा के मॉडल को जहाँ सिम्प्लीफाय (Simplify) किया गया है वहीं जरूरत के अनुसार अम्प्लीफाय (Amplify) भी** किया गया है। जहां भी क्लासिफाय (Classify) करने की ज़रूरत थी वहाँ **क्लासिफाय** किया गया है और जहाँ नहीं थी वहाँ डिक्लासिफाय (Declassify) भी किया गया है। शिक्षा के **टेम्पररी करैक्टर (Temporary Character) को हटाकर कंटेम्पररी (Contemporary) बनाने** की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक ओर **हम इंडियन फाउंडेशन (Indian Foundation) पर खड़े होंगे वहीं हमारी आउटलुक इंटरनेशनल** होगी। दोनों के बीच संतुलन का नई शिक्षा नीति में विशेष ध्यान रखा गया है।

आज इस स्कूल शिक्षा कनक्लेव के अवसर पर मैं **माननीय प्रधानमंत्री जी** का **धन्यवाद** करता हूँ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक निरंतर संवाद और चर्चा के जरिये देश तथा मंत्रालय को मार्ग-दर्शन दे रहे हैं।

इस पूरे एजुकेशन कॉन्क्लेव को हमने **कुछ खास सत्रों में बांटकर** एक सामूहिक परिचर्चा का केंद्र बनाया है। इन सत्रों की एक संक्षिप्त चर्चा भी मैं आपसे यहां करना चाहूंगा-

जैसे कि **बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (foundational literacy and numeracy)** - कक्षा 1 से 3 तक प्रारंभिक भाषा तथा गणितीय कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2025 तक **'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन'** की स्थापना की जाएगी। **इसमें पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनती करने, अंकगणित और गणितीय सोच पर ध्यान केंद्रित करने; बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्च क्वॉलिटी वाले संसाधनों का विकास; शिक्षक रिक्तियों को भरना; पीयर-ट्यूटरिंग** जैसी पहल की जाएगी। सच्चाई तो यह है कि **हर छात्र को स्कूल तक ले जाना है और हर छोर तक शिक्षा को पहुंचाना** ही हमारा संकल्प है। शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे शक्तिशाली प्रयोग माना गया है। जिस बदलाव व प्रगति की हम आशा करते हैं उसका रास्ता शिक्षा और विशेष रूप से स्कूली शिक्षा से होकर ही गुजरता है। कहा भी जाता है कि बुनियाद जितनी मजबूत होगी, वो इमारत भी

उतनी ही बुलंद होगी। छात्रों में प्रारंभ से ही निवेश करना होगा ताकि हम एक मजबूत पीढी का निर्माण कर सकें।

इसी तरह **आर्ट इंटीग्रेटेड एंड टॉय इंटीग्रेटेड पेडागोगी** पर भी एक सत्र है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यह कला और खेल-खिलौने के माध्यम से **सीखने की प्रक्रिया को न केवल आसान बनाना है बल्कि हैप्पीनेस, समृद्ध तथा शिक्षण को बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए अंकित कर देता है।** यह ऐसी शिक्षा पद्धति है जो बच्चों को एक समूह में सीखना और काम करना सिखाती है। इससे ना केवल बच्चों की पांचों इंद्रियों मजबूत होती हैं बल्कि उनमें वैज्ञानिक स्वभाव और सामुदायिकता की भावना भी विकसित होती है।

अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसीई के बात करें तो- एनईपी 2020 में वर्ष 2025 तक 3-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर बल दिया गया है। एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए **प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक रूपरेखा (NCPFECCE)** तैयार की जाएगी। प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा की योजना बनाने और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा **संयुक्त रूप** से किया जाएगा।

यह शिक्षा नीति एक मूलभूत बात को आगे ले जाती है। **कैपेसिटी बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग का फार्मूला ही है जो हमें सशक्त बनाएगा। चाहे छात्रों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो या फिर शिक्षकों की या फिर संस्थानों की।** सभी का साथ लिए बिना नेशन बिल्डिंग का काम संभव नहीं था। इसी को आधार बनाकर **10+2 को 5+3+3+4 में बदलने का निर्णय** लिया गया।

आगे बढ़े तो शिक्षा को अब हम **प्रोग्रेस कार्ड कहेंगे जो 360° हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा। सही मायनों में हम एक मुखी आकलन से चहुंमुखी आंकलन** की तरफ बढ़ेंगे। यह शिक्षा, सहभागिता एवं संवेदना की त्रिवेणी होगा। इसमें ना केवल **अकादमिक आयामों की बल्कि सामाजिक एवं भावनात्मक समझ की प्रक्रिया** का भी उचित मूल्यांकन होगा। **जहां एक ओर इनपुट (Input) का आकलन होगा वहीं आउटपुट (Output) का भी आकलन इ**स नीति के तहत किया जायेगा। **लर्निंग आउटकम (Learning Outcome)** को वैज्ञानिक तरीकों से जाँचा, परखा और तय किया जाएगा। **Target based action plan तैयार किया जायेगा जो एक टाइमलाइन (Timeline)** को लेकर आगे बढ़ेगा।

भाषा की दृष्टि से बात करें तो भारतीय भाषाओं का प्रचार एवं संरक्षण, संवृद्धि और जीवंतता को सुनिश्चित करने के लिए, कई पहलों की परिकल्पना की गई है। अधिक से अधिक

उच्चतर शिक्षा संस्थाएं और उच्चतर शिक्षा के अधिक से अधिक कार्यक्रम, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा / स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे। एक **भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान (आईआईटीआई)** की स्थापना की जाएगी। शास्त्रीय, जनजातीय और लुप्तप्राय भाषाओं सहित **सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ावा देने** के प्रयास किए जाएंगे।

नो हार्ड सेपरेशन जैसा सत्र यह स्पष्ट करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर में हमारी शिक्षा नीति आधुनिकता की सारे आयामों के साथ **बहु विषयक और बहुभाषी पक्षों** को भी लेकर चल रही है। **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence)** हमारी पीढ़ी को **इफेक्टिव इंटेलिजेंस (Effective Intelligence)** की ओर ले जाये इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। हर एक फैसले को एक ही पैमाना मानकर हम आगे बढ़ेंगे। **"छात्र ही हमारी रणनीति के Centre of Gravity (केंद्रबिंदु)"** हैं। इसी प्रगतिवादी सोच को सामने रखकर ही स्कूली शिक्षा में मूलभूत बदलाव किए गए हैं। हमारी नीति में **करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर या को- करिकुलर या फिर आर्ट, ह्यूमैनिटी, साइंस, वोकेशनल, एकेडमिक जैसा कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं है,** यानी सभी को समान महत्व दिया गया है। यह **फ्लैक्सिबिलिटी ही हमारी नीति को क्रेडिबिल और एडेप्टेबल** बनाती है।

भविष्य का सोचे तो हम उस युग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक पेशे में ही नहीं टिका रहेगा। ऐसे में निरंतर खुद को **रि-स्किल और अप-स्किल** करते रहना होगा, जिसके लिए प्रत्येक छात्र को सक्षम बनाने की आवश्यकता है। तकनीकी के दौर में चाहे हमारे कंप्यूटर या मोबाइल हों या फिर छात्र अथवा शिक्षक खुद को अपडेट रखना ही होगा। वरना आउटडेट (Outdate) होने का भय रहेगा। **नई शिक्षा नीति हर स्तर पर खुद को स्किल एवं वोकेशन ट्रेनिंग के जरिये अपडेट रखने** में मदद देगी। अपग्रेड करते रहने की संस्कृति एवं सोच के साथ यह शिक्षा नीति आगे बढ़ने की दिशा में अद्भुत परिणाम देगी।

एक्सेस से असेसमेंट तक, इंक्लूशन से इंटीग्रेशन तक, प्राथमिक शिक्षा से रिसर्च तक, **थिंकिंग से थॉट प्रोसेस तक** की यात्रा इस शिक्षा नीति के माध्यम से तय होगी।

अगर कार्यान्वयन की बात करें तो **Policy Formation एक अलग विषय है और पालिसी इम्प्लीमेंटेशन** अलग विषय है। इन दोनों के बीच सबसे अहम रोल **लीडरशिप** का होता है। ऐसी लीडरशिप जो नीति को ज़मीन पर उतार सके। मैं आशा करता हूँ कि **शिक्षक से लेकर अभिभावक तक, संस्थानों से लेकर शिक्षाविदों तक, सचिव से लेकर शिक्षामंत्री तक हम सब मिलकर अपने स्तर पर इस नीति को वो नेतृत्व दें, दिशा दें और क्रियान्वयन करें** जिससे हम राष्ट्रीय स्तर पर एक क्रांतिकारी बदलाव ला पाएं। उस बदलाव को जिसका इंतज़ार देश पिछले 75 वर्षों से कर रहा था।

शिक्षा में राज्यों की भूमिका सर्वोपरि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्यों को संविधान के समवर्ती प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार देती है। हमें **केंद्र और राज्यों के स्तर पर व्यापक, सुनियोजित और मिलजुल कर रणनीति बनानी** होगी। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद एक नए और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण, NCERT द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए **NCERT द्वारा तैयार प्रारूप पर चर्चा शुरू करने के लिए राज्य स्तर पर समितियाँ गठित** की जाएं। जिससे राज्य पाठ्यचर्या भी साथ-साथ तैयार किया जा सके।

एनईपी 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने एनईपी की प्रत्येक सिफारिश को जिम्मेदार एजेंसियों के साथ **एक मिशन मोड में और समय सीमा के साथ जोड़ते हुये एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना** तैयार की है। इस कार्यान्वयन योजना का मुख्य फोकस गतिविधियों को इस तरह से परिभाषित करना है कि एकजुट कार्यान्वयन तैयार किया जाए और केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त क्रियान्वयन किया जा सके।

इस कार्य सूची/कार्यान्वयन योजना में नीति की भावना और सहयोगात्मक संघवाद जैसी बुनियादी बातों का ध्यान रखा गया है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है ।

अध्यायवार टास्क लिस्ट को आने वाले दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा और राज्यों से अनुरोध किया जाएगा कि वे इस बारे में एक निर्धारित अवधि के भीतर अपने सुझाव दें। जिस प्रकार का विस्तृत विमर्श, मंथन और चिंतन नीति के प्रथम चरण में हमें मिला वैसी ही समावेशी सोच के साथ क्रियान्वयन में भी हमें **सबका साथ, सबका विश्वास** मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है कि इससे जमीनी स्तर की वास्तविकताओं के साथ नीति को जोड़ने वाली कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी विषयवार कार्यान्वयन समितियों का भी गठन करेगा। इन कार्यान्वयन समितियों में मंत्रालय, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओएस, एनसीटीई, केवीएस, जेएनवी और अन्य संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। **ये कार्यान्वयन समितियां इस कार्यान्वयन योजना को सभी से प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम रूप देंगी तथा नीति के वास्तविक कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करेंगी।**

मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के सभी कोने में रह रहे हमारे सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और देश का हर छात्र शिक्षित मानव सम्पदा के रूप में एक ताकत बनकर आत्मनिर्भर, शिक्षित और सशक्त भारत के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। हम

इसे लागू करने के लिये आप सभी के सहयोग, समन्वय, सहभागिता और नेतृत्व की अपेक्षा करते हैं ।

मै सभी राज्यों का भी आह्वान करना चाहूँगा कि वे भी सभी हितधारकों - अभिभावकों, शिक्षकों, स्कूलों, छात्रों, शिक्षाविदों आदि से सुझाव लें, चर्चा करे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए **जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम** प्रारम्भ करें। जागरुक नागरिक, सचेत अभिभावक, शिक्षकों और छात्रों के सहयोग से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। हर छात्र, हर शिक्षक, हर संस्थाएं, हर एक प्रदेश सरकार हमारी इस नीति के **ब्रांड एंबेसडर** हैं। अंततः **यह पूरे राष्ट्र के विमर्श एवं चिंतन के बाद पूरे राष्ट्र की आकांक्षाओं को समेटे हुए, राष्ट्र की शिक्षा नीति है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम अवश्य सफल होंगे**।

बहुत-बहुत आभार
धन्यवाद